



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 136-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 3, 2017 (SRAVANA 11, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

संशोधन

दिनांक 3 अगस्त, 2017

संख्या-सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/टी०ओ०डी०/2017/18927.- यातायात उन्मुख विकास (टी०ओ०डी०) से सम्बन्धित पॉलिसी अधिसूचना संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/(टी०ओ०डी०)/2016/343, दिनांक 09 फरवरी, 2016 द्वारा अधिसूचित की गई थी बाद में संशोधन अधिसूचना संख्या टी० एण्ड० सी०पी०/टी०ओ०डी०/2016/25294, दिनांक 16 नवम्बर 2016, अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/(टी०ओ०डी०)/2017/964 दिनांक 11 अप्रैल 2017, तथा अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/(टी०ओ०डी०)/2017/12909, दिनांक 13 जून, 2017 द्वारा अधिसूचित किए गए थे दिनांक 9 फरवरी, 2016 की पॉलिसी दिनांक 25-07-2017 को मंत्री परिषद् की बैठक में आगे पुनरीक्षित की गई है तथा निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए हैं जो निम्न अनुसार है:-

1. खंड 7 में “टी.ओ.डी. क्षेत्र के भीतर आयोजना माणक (ग्रांडड कवरेज/एफ.ए.आर.)” तीव्र तथा संक्रांति क्षेत्र के लिए संघटित वाणिज्यक/कार्यालय स्थान तथा मिश्रित भू-भाग में अधिकतम भूमि आवृत्त क्षेत्र में क्रमशः 60% तथा # 50% के रूप में पढ़ा जाएं
2. संशोधित नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****AMENDMENT**

The 3rd August, 2017

No. CCP (NCR)/TOD/2017/18927.— The policy relating to ‘Transit Oriented Development (TOD)’ was notified *vide* Notification No. CCP (NCR)/TOD/2016/343 dated the 9th February, 2016. Subsequent amendments were notified *vide* Notification No. T&CP/TOD/2016/25294 dated the 16th November, 2016; Notification No. CCP (NCR)/TOD/2017/964 dated the 11th April, 2017 and Notification No. CCP (NCR)/TOD/2017/12909 dated 13th June, 2017. The policy dated the 9th February, 2016 has been further reviewed by the Council of Ministers in its meeting held on 25th July, 2017 and approved the following amendments which is as under:-

1. In clause 7 “Planning Parameter (Ground Coverage/FAR) within TOD Zone” the maximum ground coverage under Intense and Transition Zone for integrated commercial/office spaces and mixed landuse be read as “50%”.
2. The amended policy will become applicable with immediate effect.

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.